

भारतीय सन्दर्भ में एंगेल्स के कालजयी चिंतन का पुनर्पाठ

प्रो. पुष्पेन्द्र दुबे

विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग

महाराजा रणजीतसिंह कालेज आफ प्रोफेशनल साइंसेस

इन्दौर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

आज देश में किसानों का सवाल प्रमुख बन गया है। महंगाई बढ़ने के बाद भी उनकी दशा में कोई सुधार न होना हमारी पूरी कृषि नीति को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सभी के माथे पर बल पड़े हुए हैं। देश के राजनीतिक दल हैरान हैं कि किसानों का सवाल अचानक उभार पर क्यों है। हमें इस प्रश्न की पड़ताल के लिए दुनिया की आर्थिक विचारधाराओं में मुख्य मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख चिंतक और दार्शनिक फ्रेडरिक एंगेल्स की ओर दृष्टिपात करने की जरूरत है। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी दृष्टि से विचार किया गया है।

प्रस्तावना

फ्रेडरिक एंगेल्स ने 15 तथा 22 नवम्बर 1894 के बीच 'फ्रांस और जर्मनी में किसानों का सवाल' विषय पर विचार व्यक्त किए थे। यह निबंध प्रगति प्रकाशन मास्को द्वारा प्रकाशित पुस्तक कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगेल्स भाग 4 में दिया गया है। पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 177 पर इसे लिखने के कारणों का खुलासा करते हुए कहा गया है कि, "एंगेल्स की रचना, फ्रांस और जर्मनी में किसानों का सवाल' किसान समस्या के बारे में एक महत्वपूर्ण मार्क्सवादी कृति है। इसे लिखने का तात्कालिक कारण यह था कि फोल्मर और अन्य अवसरवादियों ने 1894 में जर्मन समाजवादी-जनवादियों की फ्रैंकफुर्ट कांग्रेस में कृषि कार्यक्रम के बारे में हुई बहस का इस्तेमाल कर धनी किसानों के समाजवादी रूपांतरण के अपने मार्क्सवाद-विरोधी 'सिद्धांत' को चुपके से प्रविष्ट करने की कोशिश की थी। एक दूसरा

कारण जिसने एंगेल्स को इस और प्रवृत्त किया यह था कि वह फ्रांसीसी समाजवादियों द्वारा की गई गलतियों को दुरुस्त करना चाहते थे। फ्रांसीसी समाजवादियों ने मार्क्सवाद से विचलित होकर मार्सई में 1892 में स्वीकृत तथा नांट में 1894 में परिवर्द्धित अपने कृषि कार्यक्रम में अवसरवाद को रियायतें दी थीं। इस आलोचना के साथ एंगेल्स ने इस पुस्तक में किसानों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में सर्वहारा वर्ग की नीति के क्रांतिकारी सिद्धांतों को विवृत किया है और मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश किसानों के बीच संश्रय के विचार को विशद रूप में प्रस्तुत किया है।"1

एंगेल्स के विचार

आज यदि एंगेल्स के विचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो लगता है कि एंगेल्स का क्रांतदर्शन केवल मार्क्स तक सीमित या उसके विचारों को जैसे-तैसे अमली जामा पहनाने का

कदापि नहीं था। जैसा कि भारत के मार्क्सवादी विचारकों में दिखाई देता है। उनकी दृष्टि में पूरी दुनिया थी। कालजयी चिंतन से यही आशय होता है कि वह किसी एक व्यक्ति, जाति, समूह, देश के लिए न होकर उसमें पूरी मानवता का समावेश हो।

किसान का सवाल मुख्य

अपने निबंध की शुरुआत वे यहीं से करते हैं कि “पूंजीवादी और प्रतिक्रियावादी पार्टियां बड़ी हैरान हैं कि क्यों समाजवादियों के मध्य सर्वत्र किसानों का सवाल इस समय सहसा कार्यसूची पर ला दिया गया है।”² फिर अगले अनुच्छेद में लिखते हैं, “राजनीतिक सत्ता के एक तत्व के रूप में किसानों ने अभी तक अधिकतर अपने को केवल अपनी उदासीनता के द्वारा ही प्रकट किया है। इस उदासीनता का मूल ग्रामीण जीवन का बिलगाव है।”³ गुलामी के दिनों में और आजादी के बाद भारत की भी यही स्थिति रही। यहां के किसान ने कभी अपने हितों की रक्षा के लिए जोरदार ढंग से आवाज ही नहीं उठायी न ही सत्ता प्रतिष्ठानों ने किसानों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनायीं।

छोटे पैमाने के उत्पादन पर खतरा

वे अपने चिंतन को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं, “पूंजीवादी उत्पादन के विकास ने कृषि-क्षेत्र के छोटे पैमाने के उत्पादन के जीवन-सूत्र काट दिए हैं, छोटे पैमाने का उत्पादन असाध्य रूप से तबाह और बरबाद हो रहा है। उत्तर और दक्षिण अमरीका के तथा भारत के प्रतिद्वन्द्वियों ने यूरोप के बाजार को सस्ते गल्ले से पाट दिया है। यह गल्ला इतना सस्ता है कि कोई घरेलू

उत्पादक इसका मुकाबला नहीं कर सकता। बड़े भू-स्वामी और छोटे-छोटे किसान दोनों ही अपने को विनाश के द्वार पर खड़ा पाते हैं। और चूंकि दोनों भूमि के स्वामी और देहात के हामी बनकर मैदान में उतरते हैं और छोटे किसान अधिकतर उन्हें इसी रूप में स्वीकार करते हैं।”⁴ एंगेल्स के समय भारत के कृषि एवं अन्य उत्पाद दूसरे देशों के मुकाबले अत्यंत सस्ते थे। आज हमारे देश के बाजार विदेशी सस्ते उत्पादों से पटे हुए हैं। खासकर पड़ोसी देश चीन ने सभी की नाक में दम कर रखा है। ऐसा ही बड़े भू-स्वामियों का है। जब भी उन पर नकेल कसने की बात आती है, वे छोटे किसानों को आगे कर अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं। सरकारी नीतियों का ज्यादा फायदा बड़े किसानों ने ही उठाया है। वह चाहे विभिन्न प्रकार के अनुदानों से संबंधित हो या आयकर में छूट से जुड़ा मामला हो। आज छोटे पैमाने का उत्पादन खतरे में है। कृषि पर बाजार का नियंत्रण होने से वह फायदे का सौदा नहीं रह गई है। अब खेती परंपरागत तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं हो रही है। नयी पीढ़ी का युवा शहरों की ओर रुख कर कृषि से इतर व्यवसायों में अपना कैरियर ढूंढ रहा है।

छोटे किसान की कसौटी

सत्ता प्राप्ति के लिए शुरू से ही राजनीतिक दल गांवों ओर रुख करते रहे हैं। एंगेल्स कहता है कि “राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करने के लिए समाजवादी पार्टी को पहले नगरों से गांवों की ओर जाना होगा, देहातों में एक शक्ति बनना होगा।”⁵ भारत सरकार द्वारा चलायी गयी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ने गांव-गांव में प्रवेश किया है। महात्मा गांधी ने देश को

आजाद कराने के लिए चर्खे का आलंबन लिया और उससे देश के लाखों गांवों तक आजादी का संदेश पहुंचाया। गांवों को साथ में लिए बिना कोई भी विचार इस देश में अमान्य होगा। अन्य देशों के समान ही भारत की देहाती आबादी में भी काफी फर्क है। यद्यपि एंगेल्स के सामने जर्मनी और फ्रांस के किसान थे, परंतु छोटे किसान वहां भी थे और यहां भी हैं। छोटे किसान पर चर्चा प्रारंभ करते हुए एंगेल्स लिखते हैं, “किसानों के बीच छोटा किसान पश्चिमी यूरोप (भारत के लिए भी) के लिए सामान्यतः सबसे महत्वपूर्ण ही नहीं है, बल्कि वह कसौटी भी है, जिसके आधार पर पूरे सवाल का ही फैसला किया जा सकता है। छोटे किसानों के बारे में एक बार अपना रुख स्पष्ट कर लें, तो हमें वह सभी तथ्य सामग्री उपलब्ध हो जाए, जिसकी कि देहाती आबादी के मुख्य संघटक हिस्सों के बारे में अपना रुख निश्चित करने के लिए हमें जरूरत है। छोटे किसान से यहां हमारा तात्पर्य भूमि के एक ऐसे टुकड़े के मालिक या काश्तकार से है, जो आम तौर से उतने से बड़ा नहीं, जितना कि वह और उसका परिवार जोत सकता है, और उतने से छोटा भी नहीं, जितने से उसके परिवार का भरण-पोषण हो सकता है। अतः यह छोटा किसान, छोटे दस्तकार की ही तरह मेहनतकश होता है। उसमें और आधुनिक सर्वहारा में अंतर यह है कि वह अब भी उत्पादन के अपने साधनों का मालिक होता है, अतः वह अतीतकालीन उत्पादन-पद्धति का अवशेष होता है।”⁶

भारत के किसान का भी उत्पादन के साधनों पर तो अधिकार है, परंतु उत्पादित वस्तु के मूल्य तय करने का अधिकार उसके हाथ में नहीं है।

कृषि के लिए उपयोगी सामग्री के लिए वह हमेशा दूसरों पर अवलंबित रहता है। आज वह अपनी छोटी-सी जोत से अपने परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो रहा है। उत्पादन के साधन होने के बाद भी उसकी दशा में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

पशुशक्ति की उपेक्षा

इससे आगे एंगेल्स लिखते हैं, “आधुनिक युग का छोटा किसान अपने भारवाही पशुओं को बिना खरीदे चारा खिलाने की संभावना से वंचित हो गया है।...अपने निजी भारवाही पशु न रख सकने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है।”⁷ भारत की कृषि व्यवस्था का मूलाधार पशुशक्ति है। गलत नीतियों के कारण कृषि से पशुशक्ति को बेदलखल कर दिया गया है। पशु के लिए उपयोगी चारे का निर्यात किया जा रहा है। उससे अन्य वस्तुएं बनायी जा रही हैं। चारे से वाहन चलाने के बेटुके प्रयोग किए जा रहे हैं। आज किसी भी किसान के लिए व्यक्तिगत ढंग से पशुपालन करना असंभव-सा हो गया है। कृषि के यंत्रीकरण से भारत के कृषि देवता बैल कत्लखाने की राह पकड़ रहे हैं। साँइल बेस्ड इकॉनामी से भारत आयल बेस्ड इकॉनामी की तरफ इतना आगे बढ़ गया है कि आज पशुशक्ति की बात करना बेमानी हो गया है।

स्वावलंबी से परावलंबी

भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देश के किसान भी स्वावलंबी थे। इस बारे में एंगेल्स लिखते हैं, “आज के किसान ने अपनी पहले की उत्पादकीय क्रिया का आधा भाग खो दिया है। पहले वह और उसका परिवार अपने ही हाथों तैयार किए गए

कच्चे माल से अपनी आवश्यकता के औद्योगिक सामानों का अधिकांश स्वयं उत्पादित कर लेता था। उसकी जरूरत के बाकी सामान गांव के पड़ोसियों से मिल जाते थे, जो खेती के अलावा कुछ दस्तकारी भी करते थे और जिन्हें कीमत अधिकतर विनिमय के सामानों या परस्पर सेवाओं के माध्यम से अदा की जाती थी। परिवार, और परिवार से भी अधिक ग्राम, स्वावलंबी थे। वे अपनी जरूरत के प्रायः सभी सामान उत्पादित करते थे। यह प्रायः अमिश्रित स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी, इसमें मुद्रा की प्रायः कोई आवश्यकता नहीं थी। पूंजीवादी उत्पादन ने अपनी मुद्रा-व्यवस्था एवं बड़े पैमाने के उत्पादन द्वारा इसका अंत कर दिया।...किसानों की हालत बराबर गिरती जाती है। करों का भार, फसल का मारा जाना, वारिसों में जायदाद का बंटवारा और मुकदमेबाजी किसानों को एक-एक कर सूदखोरों के मुंह में झोंके दे रहे हैं। ऋणग्रस्तता अधिकाधिक आम बनती जाती है और प्रत्येक के ऊपर ऋण की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। संक्षेप में, अतीतकालीन उत्पादन-पद्धति के अन्य सभी अवशेषों की भांति हमारे छोटे किसान का विनाश भी निश्चित है, उसके उद्धार की कोई आशा नहीं है। वह भावी सर्वहारा है।”⁸

आज देश के शहरों में बढ़ती आबादी इसी तथ्य की ओर इंगित कर रही है। यह आबादी गांवों से शहरों की ओर आ रही है। पिछले दस वर्षों में देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने किसानों की भलाई के लिए हजारों करोड़ रुपये के पैकेज देने की घोषणा की।

मध्यप्रदेश में मौसम की मार और अन्यान्य कारणों से पिछले पांच-छः सालों में आठ हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। ऊपर के वक्तव्य को देखकर लगता है कि एंगेल्स यूरोप के बारे में नहीं बल्कि भारत के किसानों का वर्णन कर रहे थे। उनकी यह घोषणा कि छोटे किसानों का विनाश निश्चित है आज प्रासंगिक हो गयी है। अंग्रेजी राज के आने तक भारत के गांव गणतंत्र थे। ब्रिटिश शासन के दौरान शहर और गांव दोनों ही गुलाम हुए। आजादी के बाद शहर तो आजाद हुए परंतु गांव गुलाम हो गए। मुद्रा व्यवस्था ने ग्रामीण जीवन को छिन्न-भिन्न कर दिया है। इस बारे में प्रसिद्ध संत विनोबा भावे लिखते हैं, “क्या अंधेर है कि किसान से लगान अनाज में नहीं लेते, और बोलते हैं कि अनाज बेचकर पैसा दो, जिसका स्थिर मूल्य नहीं। अनाज में जो पोषक तत्व सौ साल पहले थे, वही आज हैं। जिसका स्थिर मूल्य है, उसे अस्थिर मूल्य में परिवर्तित करने के लिए कहते हैं। मैं यह समझ नहीं सकता।”⁹

जमीन बचाना कठिन

आज किसान के लिए अपनी जमीन की हिफाजत करना दिनोंदिन कठिन होता जा रहा है। एंगेल्स किसानों को बचने का रास्ता बताते हुए कहते हैं कि, “किसान को समाजवादी प्रचार पर तत्परता से कान देना चाहिए”¹⁰ परंतु वे स्वयं इस बात को जानते थे कि किसान की गहरी संपत्ति की भावना उसे ऐसा करने से रोके हुए है। “खतरे में पड़े जमीन के अपने नन्हें से टुकड़े की हिफाजत करना उसके लिए जितना ही अधिक कठिन होता जाता है, उतना ही अधिक वह उससे जी-जान से चिपटता जाता है, और उतना ही अधिक वह भू-

संपत्ति को पूरे समाज को हस्तांतरित करने की बातें करने वाले समाजवादी-जनवादियों को सूदखोरों और वकीलों की तरह खतरनाक समझने लगता है।”¹¹

स्वामित्व का प्रश्न

उत्पादन के साधनों के स्वामित्व को लेकर एंगेल्स ने क्रांतिकारी विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने लंदन की स्थिति का वर्णन भी किया है, जो भारत जैसे देश पर पूरी तरह लागू होती है। “अलग अलग उत्पादकों द्वारा उत्पादन के साधनों का स्वामित्व अब के जमाने में इन उत्पादकों को असली स्वतंत्रता नहीं प्रदान करता। नगरों में दस्तकारी तबाह और बरबाद हो चुकी है, लंदन जैसे महानगरों में तो वह संपूर्णतया लुप्त हो चुकी है, वहां बड़े पैमाने के उद्योग, पसीना-निचोड़ मशककत प्रणाली और दिवालियापन पर फूलने-फलने वाले नालायकों ने उसे हटाकर उसकी जगह ले ली है। न तो स्वावलंबी छोटे किसान का अपने नन्हे से खेत का स्वामित्व सुरक्षित है, न ही वह स्वतंत्र है। वह और उसका घर, उसके खेत-खलिहान सूदखोर के हो चुके हैं, उसकी जीविका सर्वहारा की जीविका से भी अधिक अनिश्चित है, सर्वहारा के तो कभी-कभी कुछ दिन शांति से कट भी जाते हैं, पर ऋणदास सदा यंत्रणा की चक्की में पिसता रहता है। दीवानी कानून की धारा 2102 रद्द कर दीजिए, कानून द्वारा यह व्यवस्था कर दीजिए कि किसान के खेती के औजारों, जानवरों आदि की एक निश्चित मात्रा कुर्की और वसूली से बरी रहेगी, तब भी आप ऐसी विशेष आपदाओं से उसे सुरक्षित नहीं कर सकते, जिनमें उसे ‘स्वेच्छापूर्वक’ अपने जानवरों को बेचने को बाध्य

होना पड़ता है और अपने शरीर तथा अपनी आत्मा दोनों को सूदखोर के हाथों में बंधक रखना पड़ता है, ताकि वह थोड़ी-सी मोहलत पाकर आराम की सांस ले सके। छोटे किसान को उसकी संपत्ति के साथ सुरक्षित रखने की आपकी चेष्टा उसके स्वातंत्र्य को नहीं, बल्कि दासत्व के उसके खास रूप को सुरक्षित बनाती है। वह एक ऐसी स्थिति को दीर्घता प्रदान करती है, जिसमें वह न जी सकता है, न मर सकता है।”¹² आज किसान परिवारों का नौकरी की तरफ रुझान जिस तेजी से बढ़ा है, उसके पीछे असुरक्षा की भावना ही है। मजदूरों की आमदनी तो फिर भी निश्चित होती है।

एंगेल्स ने एक बात और कही है कि “उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व स्थापित करने के लिए सर्वहारा को हर उपलब्ध उपाय के जरिये जरूर संघर्ष करना चाहिए।”¹³

अब यहां ‘हर उपलब्ध उपाय’ में हिंसा का समावेश भी हो जाता है। सामूहिक स्वामित्व के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि पूंजीपति वर्ग को अपने रास्ते से हटाना भी पड़े तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। इससे यही बात ध्वनित होती है। “अपनी पार्टी में हम किसी भी वर्ग के व्यक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, पर पूंजीवादी, मध्यम पूंजीवादी या मध्यम किसान हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी समूह का पार्टी में उपयोग नहीं हो सकता।”¹⁴

सर्वोदय विचार यहां इस रूप में भिन्न हैं कि उसका विश्वास हृदय परिवर्तन पर है। वह अमीरों से अपनी अमीरी कम करने को कहता है। वह आज की पार्टी व्यवस्था से ऊपर का विचार है।

एंगेल्स ने उत्पादन के साधनों का सम्मिलित स्वामित्व ही एकमात्र प्रधान लक्ष्य निर्धारित किया। उसी के लिए प्रयास करने की जरूरत बताई। केवल उद्योग में ही नहीं वरन् कृषि में भी सामूहिक स्वामित्व स्थापित करना है। इस सम्मिलित स्वामित्व का स्वरूप सर्वोदय में भिन्न है। व्यक्तिगत स्वामित्व हो नहीं सकता और राज्य को स्वामित्व सौंप नहीं सकते। स्थानीय समूह का स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर हो सकता है, जिससे मनुष्य अपनी दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

संपत्ति और श्रम

आज संपत्ति और श्रम अलग-अलग हैं। जिनके पास संपत्ति है, वे श्रम से दूर भागते हैं और जिनके पास श्रम है वे संपत्तिविहीन हैं। एंगेल्स लिखते हैं, “समाजवाद का यह काम नहीं है कि संपत्ति को श्रम से अलग करे, उलटे उसका काम यह है कि समग्र उत्पादन के इन दो उपकरणों को एक ही हाथ में रखकर उन्हें संयुक्त करे।...समाजवाद का काम उत्पादन के साधनों को उत्पादकों के हाथ में, उनकी सम्मिलित संपत्ति के रूप में अंतरित करना है।...निस्संदेह समाजवाद किसानों की संपत्ति के झूठे दिखावे को मिटाने में दिलचस्पी रखता है।”¹⁵

भूमि का प्रश्न सदियों पुराना है। महाभारत इसीलिए हुआ कि सुई की नोंक के बराबर भूमि देने से इंकार कर दिया गया था। भूमि का प्रश्न हल किए बिना कोई भी मसला सुलझने वाला नहीं है। भूमि की व्यक्तिगत मालिकियत नहीं हो सकती। इसलिए भारत में कहा गया, ‘सबै भूमि गोपाल की’। आज भूमि की मालिकियत को

सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बना दिया गया। अनेक संतों ने, राजा-महाराजाओं ने भूमि के प्रश्न को हल करने के लिए कई प्रयत्न किए। उनमें ऋषि मार्क्स का योगदान भी है। उनके बाद संत विनोबा का नाम आता है। उन्होंने संपत्ति के झूठे दिखावे को मिटाने और करुणा का प्रसार करने के लिए भूदान आंदोलन चलाया। उसकी परिणति ग्रामस्वराज्य के विचार में हुई। यह श्रम की पुनर्स्थापना का विचार है।

कंपनी कल्टीवेशन

माल का महकमा, सूदखोर और नवोदित बड़े-बड़े जमींदार वे साधन ही तो हैं, जिनके जरिये पूंजीवादी उत्पादन यह अवश्यम्भावी विनाश निष्पन्न करता है। आज ‘कंपनी कल्टीवेशन’ की वकालत जोर-शोर से की जा रही है। एक ही प्रकार की फसल हजारों हेक्टेयर में लगाई जा रही है। कंपनियां सीधे ही खेत से फसल ले रही हैं। प्रारंभ में किसानों को लगता है कि यह बहुत बढ़िया धंधा है, परंतु कुछ समय बाद उसकी असलियत सामने आ जाती है। एंगेल्स ने इसका विश्लेषण करते हुए लिखा है, “उत्तरी फ्रांस में किसानों को चुकंदर की ही खेती करने की बाध्यता के साथ अत्यंत दुःसह शर्तों पर जमीन पट्टे पर दी जाती है। उन्हें अपना चुकंदर निर्धारित मिल को मिल द्वारा निश्चित भाव पर देना होता है, खास बीज ही खरीदना पड़ता है, किसी निर्धारित खाद की निश्चित मात्रा इस्तेमाल करनी होती है और इस सबके बाद जब वे मिल में चुकंदर पहुंचाते हैं, तो वहां बुरी तरह ठगे जाते हैं।”¹⁶

सूदखोरी

आज भारतीय किसान सूदखोरों के चंगुल में फंसा हुआ है। भारत सरकार ने किसानों के 75 हजार करोड़ के ऋण माफ किए। इसके बाद भी एक अनुमान के अनुसार देश के 22 प्रतिशत किसान निजी सूदखोरों से ब्याज पर पैसा लेते हैं। इनसे मुक्ति की कोई सूरत नजर नहीं आती। इस पर एंगेल्स ने लिखा है, “सूद की कानूनी और रिवाजी दर को घटाने की मांग करना, सूदखोरी के विरुद्ध नये सिरे से कानून पास करना होगा। यह आरक्षण संबंधी ऐसी कार्रवाई करने की नये सिरे से चेष्टा करना है, जो पिछले दो हजार वर्षों से सर्वत्र और सदा सिद्ध होती आ रही है। यदि कोई छोटा किसान अपने को ऐसी स्थिति में पाये, जहां सूदखोर के पास जाना ही उसे कम अनिष्टकर जात हो, तो सूदखोर सूदखोरी संबंधी कानूनों के चंगुल में आये बिना उस किसान का खून चूसने के तरीके हमेशा निकाल लेगा। अधिक से अधिक इस कार्रवाई से छोटे किसान को सांत्वना भर प्राप्त हो सकती है, - उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता। बल्कि उन्हें सख्त जरूरत के वक्त ऋण प्राप्त करने में और भी कठिनाई हो जाएगी।”¹⁷

सूदखोरी की समस्या वैश्विक है। दुनिया का कोई किसान इससे अछूता नहीं है। भारत के निम्नवर्ग के किसान की हालत तो अत्यंत दयनीय है। इसका चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास ‘गोदान’ में बखूबी किया है। अधिकतर कानून बड़ी जमींदारियों (अब बड़े भूमालिकों) के पक्ष को ही मजबूत करते हैं। भारतीय किसान संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर भोपाल में किए गए आंदोलन में प्रस्तुत मांगे भी छोटे किसानों के लिए सब्जबाग साबित हुई हैं। उन मांगों में कुछ भी निश्चित नहीं है।

हमारे देश में आम चुनाव आते ही हवा में किसानों के लिए अनेक प्रकार के नारे उछाले जाते हैं। आश्वासन दिए जाते हैं। देश के सभी राजनीतिक दल एक ही झटके में किसान समूह को अपने पक्ष में कर लेना चाहते हैं। एंगेल्स इस बात से साफ इंकार करते हैं कि, “हमारा हित इस बात में नहीं है कि किसानों को रातोंरात अपनी ओर कर लें, ताकि अगले ही दिन हमारे अपने वादे पूरे न हो सकने के कारण वे हाथ से निकल जायें। जिस तरह सदा के लिए स्वामी बनने का स्वप्न देखने वाला छोटा दस्तकार पार्टी सदस्य के रूप में हमारे लिए बेकार है, उसी तरह वह किसान भी बेकार है, जो यह आशा करता है कि हम छोटी जोत रूपी उसकी संपत्ति को स्थायित्व प्रदान करेंगे।”¹⁸

एंगेल्स के इस बारे में बहुत दृढ़ विचार थे कि छोटे किसानों का विनाश अवश्यम्भावी है। उनके पास इस दृढ़ता के कारण भी थे। लेकिन वे इस बात से इंकार भी करते हैं कि हमारा यह काम नहीं है कि अपनी ओर से किसी तरह का हस्तक्षेप करके उस दिन को नजदीक लायें। दूसरे, यह भी उतना ही स्पष्ट है कि जब हमारे हाथों में राज्य-सत्ता आएगी, तब हम बलपूर्वक छोटे किसानों की संपत्ति (बामुआवजा या बिला मुआवजा) छीनने की - जो काम हमें बड़े जमींदारों के मामले में करना पड़ेगा - बात नहीं सोचेंगे। छोटे किसानों के संबंध में हमारा कार्य प्रथमतः उनके निजी उद्यम और निजी स्वामित्व को सहकारी उद्यम और स्वामित्व में अंतरित करना होगा, और यह ‘बलपूर्वक’ नहीं, बल्कि उदाहरण पेश करके तथा सामाजिक सहायता देकर किया जाएगा।”¹⁹ यह बिंदु बहुत

महत्वपूर्ण है कि कोई भी काम जोर-जबर्दस्ती से नहीं किया जाएगा। आज सरकारें और गांव के असंतुष्टों में संघर्ष छिड़ा हुआ है। सरकारें बंदूक की नोक से शांति स्थापित करना चाहती हैं और असंतुष्ट उसका जवाब बंदूक से दे रहे हैं। एंगेल्स साफ कहते हैं कि उस समय छोटे किसानों को ऐसे भावी लाभ, जो उन्हें आज भी स्पष्ट होंगे, दिखाने के हमारे पास प्रचुर साधन होंगे।

सहकारिता

एंगेल्स इस बारे में बिलकुल निश्चित थे कि किसानों के घरों और खेतों को सहकारिता के आधार पर संचालित सहकारी संपत्ति में परिवर्तित करके ही हम उन्हें उनके लिए बचा और बरकरार रख सकते हैं। व्यक्तिगत स्वामित्व पर निर्भर व्यक्तिगत कृषि ही किसानों का विनाश अवश्यम्भावी बनाती है। यदि वे व्यक्तिगत संचालन पर अड़े रहेंगे, तो वे अनिवार्यतः घर-द्वार से निकाल बाहर किए जाएंगे और पूंजीवादी, बड़े पैमाने का उत्पादन उनकी पुरानी-धुरानी उत्पादन पद्धति का स्थान ग्रहण कर लेगा। यही वस्तुस्थिति है। इस में हम उन्हें स्वयं बड़े पैमाने का उत्पादन करने का और पूंजीपतियों के खाते नहीं, बल्कि स्वयं अपने खाते, अपने सम्मिलित खाते, करने का अवसर प्रदान करते हैं। किसानों को समझाना है कि यह उनके हित में है, कि यही उनके उद्धार का एकमात्र मार्ग है क्या असंभव होगा ?²⁰

आश्वासन नहीं दे सकते

यह बात आज की तारीख में भारत में पूर्णतः लागू होती है कि, “छोटी जोत वाले किसानों को हम न तो आज और न ही भविष्य में कभी यह

आश्वासन दे सकते हैं कि पूंजीवादी उत्पादन की प्रचण्ड शक्ति से उनकी व्यक्तिगत संपत्ति और उनके व्यक्तिगत उद्यम की रक्षा की जा सकती है। हम उन्हें इतना आश्वासन दे सकते हैं कि हम बलपूर्वक, उनकी इच्छा के विरुद्ध, उनके संपत्ति संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा, हम इस बात की हिमायत कर सकते हैं कि आइंदा छोटे किसानों के विरुद्ध पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों का संघर्ष अनुचित साधनों का कम से कम इस्तेमाल करते हुए चले और सीधे-साधे की जाने वाली लूट-खसोट और ठगी, जो आजकल धड़ल्ले से चलती है, जहां तक संभव हो, बंद हो जाए।”²¹

ईमानदारी और ठगी

भारत ने जब से वैश्विक बाजार में प्रवेश किया है, तब से भ्रष्टाचार, घोटालों और ठगी की घटनाएं बढ़ गई हैं। नेतृत्व पर सवालिया निशान लग गया है। एंगेल्स इसे पूंजीवाद की देन बताते हैं। “विकसित पूंजीवादी उत्पादन-पद्धति में यह कोई भी नहीं बता सकता कि ईमानदार और ठगी की सीमारेखा कहां पर है। पर इससे अवश्य बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि सार्वजनिक सत्ता किस ओर है - ठगे जाने वालों की ओर या ठगने वालों की ओर।”²²

आज भारत में यह तथ्य बड़ा प्रासंगिक हो गया है। आज सत्ता प्रतिष्ठान घोटालेबाजों, ठगों को बचाने का जतन कर रहे हैं। जनता टुकुर-टुकुर देख रही है कि उनके गाढ़े पसीने की कमाई को अपने ऐशो-आराम में उड़ाने वाले जेल की सलाखों के पीछे कब जाते हैं।

एंगेल्स यह नहीं चाहते कि सभी को सर्वहारा बना दिया जाए। वे लिखते हैं कि, “सर्वहारा की पांतों में जबरन ढकेले जाने से हम जितने ही अधिक किसानों को बचा सकें, जितने अधिक को किसान रहते हुए ही हम अपनी ओर कर सकें, उतनी ही जल्दी और आसानी से सामाजिक कायापलट संपन्न होगा। इस कायापलट को तब तक टालने से, जब तक कि पूंजीवादी उत्पादन सर्वत्र अपनी चरम परिणति पर न पहुंच जाये और हर छोटा दस्तकार और हर छोटा किसान पूंजीवादी, बड़े पैमाने के उत्पादन का शिकार न बन जाये, हमारा कुछ काम नहीं बनने का।”²³

अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए एंगेल्स अपने साथियों को यह हिदायत देते हैं कि, “हमारी पार्टी का यह कर्तव्य है कि किसानों को बारंबार स्पष्टता के साथ जताये कि पूंजीवाद का बोलबाला रहते हुए उनकी स्थिति पूर्णतया निराशापूर्ण है, कि उनकी छोटी जोतों को इस रूप में बरकरार रखना एकदम असंभव है, कि पूंजीवादी, बड़े पैमाने का उत्पादन उनकी छोटे उत्पादन की अशक्त, पुरानी-धुरानी प्रणाली को उसी तरह कुचल देगा, जिस तरह रेलगाड़ी ठेलागाड़ी को कुचल देती है। ऐसा करके हम आर्थिक विकास की अनिवार्य प्रवृत्ति के अनुरूप कार्य करेंगे। और यह विकास एक न एक दिन छोटे किसानों के मन में हमारी बात को बैठाये बिना नहीं रह सकता।”²⁴

यह विचार सर्वोदय विचार के एकदम नजदीक है। आज भारत देश की परंपरागत कृषि पद्धति को खतरा पैदा हो गया है। कृषि के निरंतर मशीनीकरण ने उत्पादन लागत को तो बढ़ा ही दिया है, छोटी जोतें मुनाफाप्रद नहीं रह गयी हैं।

फलतः वे किसान पूंजीवाद के अदृश्य दुष्चक्र में फंस गए हैं।

विदेशी होड़ का शिकार

एंगेल्स यह भी कहते हैं कि, “यदि ये किसान यह गारंटी चाहते हैं कि उनका उद्यम जारी रहे, तो ऐसा आश्वासन देने की स्थिति में हम नहीं हैं। वे तब वे यहूदी विरोधियों, किसान संघ वालों और ऐसी ही अन्य पार्टियों में शामिल होंगे, जिन्हें सब कुछ वादा करने और एक भी वादा पूरा न करने में मजा आता है। हमें आर्थिक दृष्टि से यह पक्कायकीन है कि छोटे किसानों की तरह बड़े और मध्यम किसान भी अवश्य ही पूंजीवादी उत्पादन और सस्ते विदेशी गल्ले की होड़ के शिकार बन जाएंगे। यह इन किसानों की भी बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता और सभी जगह दिखायी पड़ रही अवनति से सिद्ध हो जाता है। इस अवनति का इसके सिवा हमारे पास कोई इलाज नहीं है कि इन्हें भी सलाह दें कि वे अपने-अपने फार्मों को एक में मिलाकर सहकारी उद्यमों की स्थापना करें, जिनमें उजरती श्रम के शोषण का अधिकाधिक उन्मूलन होता जाएगा, और जो धीरे-धीरे उत्पादकों के एक महान् राष्ट्रीय सहकारी उद्यम की शाखाओं में परिवर्तित किए जा सकते हैं, जिनमें प्रत्येक शाखा के अधिकार और कर्तव्य समान होंगे। यदि ये किसान यह महसूस करें कि उनकी मौजूदा उत्पादन-पद्धति का विनाश अवश्यम्भावी है और इससे आवश्यक सबक हासिल करें, तो वे हमारे पास आएंगे और यह हमारा कर्तव्य हो जाएगा कि परिवर्तित उत्पादन-पद्धति में उनके भी संक्रमण को अपनी शक्ति भर सुगम बनायें। अन्यथा हमें उन्हें अपने भाग्य के भरोसे छोड़ देना और उनके उजरती मजदूरों

के पास जाना होगा, जिनके बीच हम सहानुभूति पाये बिना नहीं रह सकते। बहुत संभव है कि यहां भी हम बलात् संपत्तिहरण करने से बाज आ सकेंगे, और इस बात का भरोसा कर सकेंगे कि भविष्य का आर्थिक विकास इन कड़ी खोपड़ियों में भी बुद्धि का प्रादुर्भाव करेगा।”²⁵

एंगेल्स को अपने विचारों पर इतना विश्वास था कि वह लेख के अंत में लिखते हैं, “यदि हमारी पार्टी के प्रसार को रोकने के लिए नयी हिंसापूर्ण कार्रवाइयां की गयीं, जैसा कि हमें धमकाया गया है, तो उनका प्रधान उद्देश्य ऐल्बा के पूरबी इलाके के ग्रामीण सर्वहारा को हमारे प्रचार से बचाना होगा। पर इससे हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत इसके बावजूद हमारी ही होगी।”²⁶

एंगेल्स के सामने यूरोप और पश्चिमी देश थे। ये वही पश्चिमी देश थे, जिन्होंने आधी दुनिया को अपना गुलाम बनाया। वहां की अकूत धन-संपदा का दोहन औद्योगीकरण के लिए किया। पश्चिमी देशों के पास उपनिवेश थे। इसलिए उन्हें तथाकथित विकास के लिए पूंजी की कमी से जूझना नहीं पड़ा। भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। यहां कृषि की कीमत पर औद्योगीकरण किया जा रहा है। इसलिए आज औद्योगिक विकास दर 23 प्रतिशत के आसपास है, जबकि कृषि विकास दर लगभग 3.5 प्रतिशत है। इसका परिणाम

सन्दर्भ

1 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 177

2 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 62

3 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 62

अमीरी और गरीबी की निरंतर बढ़ती खाई में दिखाई दे रहा है। हमारे देश की ताकत किसान हैं, जिनकी हमने लगातार उपेक्षा की है। खेती के साथ जुड़े हुए ग्रामोद्योगों को हमने जानबूझकर समाप्त किया है। किसान के पास खेती के अलावा वैकल्पिक आमदनी का कोई जरिया नहीं रह गया है। जिससे वह कर्ज के दलदल में फंसकर आत्महत्या करने पर मजबूर है। “आज जब किसानों को खेती ही लाभदायक नहीं मालूम होती, तो खादी कहां से लाभदायक मालूम होगी ? सारा जीवन ही उन्हें लाभदायक मालूम नहीं होता। वे आत्महत्या नहीं कर सकते, इसलिए जीते हैं। इसलिए, ग्रामीण जीवन में, देहात की जिंदगी में रस कैसे पैदा हो, ग्रामीणों की दिलचस्पी जीवन में कैसे बढ़े, यह मुख्य सवाल है। ग्रामीण जीवन सुंदर, सुखमय और जीनेलायक हो सकता है, यह हमें दिखाना होगा।”²⁷

ऐसा ही भरोसा संत विनोबा को है। उन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया है कि साम्ययोग की स्थापना हुए बिना दुनिया में शांति कायम होना संभव नहीं है। उन्होंने साम्यवाद और सर्वोदय विचार के समन्वय से साम्ययोग यह नया शब्द बनाया है। यह उनका मौलिक विचार है। आज की परिस्थितियां इसी ओर इंगित कर रही हैं कि भारत देश के गांवों को मजबूत करके ही हम अपनी स्वतंत्रता कायम रख सकते हैं।

4 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 63

5 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 63

6 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 65



- 7 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 66
- 8 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 66
- 9 साम्ययोगी समाज: विनोबा साहित्य खण्ड 18: सम्पादक गौतम पृष्ठ 150
- 10 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 67
- 11 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 66
- 12 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 71
- 13 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को 71
- 14 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 74
- 15 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 72
- 16 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 73
- 17 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 77
- 18 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 79
- 19 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 79-80
- 20 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 81
- 21 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 81
- 22 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 81-82
- 23 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 82
- 24 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 82-83
- 25 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 85
- 26 मार्क्स एंगेल्स: भाग 4: प्रगति प्रकाशन मास्को पृष्ठ 87
- 27 साम्ययोगी समाज: विनोबा साहित्य:: खण्ड 18 संपादक गौतम पृष्ठ 66